GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COAL

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 63
TO BE ANSWERED ON 10.02.2025

INVESTIGATION OF COAL SCAM

*** 63 Smt. Priyanka Chaturvedi**

Will the Minister of **Coal** be pleased to state:

(a) the status of investigation of the 2018 coal scam worth ₹ 6000 crore involving large companies;

(b) whether Government has received any additional evidence recently related to the scam, and if so, the details thereof;

(c) whether Government has released guidelines, mandates, or certifications for calorific value testing agencies to prevent mis-reporting; and

(d) the steps taken by Government to prevent such scams in future?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL AND MINES
(SHRI SATISH CHANDRA DUBEY)

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED IN REPLY TO PARTS (A) to (D) IN RESPECT OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 63 FOR REPLY ON 10.2.2025 REGARDING ‘’INVESTIGATION OF COAL SCAM’’ ASKED BY SMT. PRIYANKA CHATURVEDI.

(a): No such scam of 2018 worth Rs.6000 crore involving large companies has been reported in the Ministry of Coal.

(b) (c) and (d): Does not arise in view of (a) above.

****

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *63

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

कोयला घोटाले की जांच

***63. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2018 के 6000 करोड़ रुपये के कोयला घोटाले, जिसमें बड़ी-बड़ी कंपनियां शामिल हैं, की जांच की क्या स्थिति है;

(ख) क्या सरकार को हाल ही में इस घोटाले से संबंधित कोई अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गलत रिपोर्टिंग को रोकने के लिए ऊष्मीय मान परीक्षण एजेंसियों के लिए दिशानिर्देश, आदेश या प्रमाणपत्र जारी किए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे घोटालों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दूबे)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"कोयला घोटाले की जांच" के संबंध में श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा दिनांक 10.02.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 63 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : वर्ष 2018 के 6000 करोड़ रु. के घोटाले, जिसमें बड़ी-बड़ी कंपनियाँ शामिल हैं, की कोई सूचना कोयला मंत्रालय में नहीं मिली है।

(ख) (ग) और (घ) : उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

****

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir, in the reply, there is one sentence that says, "No such scam of 2018 worth Rs. 6,000 crore involving large companies has been reported in the Ministry of Coal." सर, आश्चर्य होता है कि वर्ष 2014 से पहले कोल स्कैम कहा जाता था, अब स्कैम को देश सेवा का जामा पहना कर बचाया जा रहा है। So, Sir, the question is this. Is it true that a certain large conglomerate had misreported the calorific value of coal and overcharged the Tamil Nadu Generation and Distribution Company? If true, what action has been taken against the conglomerate and the third party testing agency that manipulated the calorific value?

कोयला और खान मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): आदरणीय सभापति महोदय, माननीया सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, इसमें कोल इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोल मिनिस्ट्री का कोई स्कैम अभी तक नहीं आया है। प्रश्न में न किसी स्कैम के बारे में बताया गया न ही किसी कम्पनी के बारे में बताया गया है। महोदय, आप देख सकते हैं कि प्रश्न में कोई clarity नहीं है, इसलिए जो जवाब दिया है, वह बराबर दिया है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary. ...*(Interruptions)*... One minute. Hon. Member, ask your supplementary with clarity. Second supplementary, Shrimati Priyanka Chaturvedi.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir, my question was extremely crystal clear, but an answer has been denied to me, in regard to the question that I had initially asked and even to my first supplementary question. He is still not answering. And, it is an RTI report which speaks about the calorific value, but I respect the Chair, Sir. So, the second question is a very specific question. Is it true that the Directorate of Revenue Intelligence found evidence of over 40 companies overcharging for imported coal and over-stating equipment value, leading to higher electricity bills? I would want to know what the status of that investigation against these allegations is. I think this is very specific, Sir. I hope for a specific answer.

श्री जी. किशन रेड्डी : आदरणीय सभापति महोदय, प्राइवेट पावर जेनरेशन कम्पनीज़, चाहे वे गवर्नमेंट की हों, पब्लिक सेक्टर की हों या स्टेट गवर्नमेंट की हों, वे जो coal import करती हैं - इनके बारे में मुझे इतना ही समझ आया कि 40 कम्पनीज़ के नाम पर investigation चल रही है। वर्तमान सप्लाई पॉलिसी के अनुसार कोल को open general license में रखा है। यह पॉलिसी वर्ष 1993 से है। इस पॉलिसी के अंदर contextual prices and applicable duty payment करके import कर सकते हैं। कोल मिनिस्ट्री संबंधित पक्षों के बीच में किसी भी imported fuel supply के संबंध में, उसके execution में शामिल नहीं होती है। इस सिस्टम के तहत वर्ष 1993 से open general licence - thermal power plants, power generation companies, coal assured

procurement करती हैं, इसमें power generation companies को पूरा अधिकार है, चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो, डोमेस्टिक कम्पनीज़ से हो और दुनिया में कहीं से भी imported coal हो, वे डायरेक्ट तय करके import करती हैं, इसके लिए आपने जो प्रश्न पूछा है ...(**व्यवधान**)... Quality Control of India...

श्री जयराम रमेश : एक ही कम्पनी इम्पोर्ट करती है।

श्री जी. किशन रेड्डी : आप मेरा जवाब पूरा हो जाने के बाद पूछिए। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, look at the Chair. ...*(Interruptions)*...

श्री जी. किशन रेड्डी : इसका मिनिस्ट्री से कोई संबंध नहीं है। यह स्टेट गवर्नमेंट का या प्राइवेट पावर कम्पनी का है। कोल इंडिया और कोल मिनिस्ट्री इसमें कोई रोल प्ले नहीं करती हैं। अभी तक हमारी एक भी complaint नहीं आई है। अभी तक हमारे यहां कोई investigation नहीं की गई है।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary; Shrimati Ranjeet Ranjan, hon. Member in the Council of States from the State of Chhattisgarh. That has relevance. Go ahead.

श्रीमती रंजीत रंजन : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या यह सही है कि हसदेव कोयला खदान, छत्तीसगढ़ के लिए लगभग 8.5 लाख पेड़ काटे जाने का प्लान है। आज की तारीख तक कितने पेड़ काटे जा चुके हैं और यह हमारे एन्वायर्नमेंट के लिए कितना घातक है? क्या यह सही है कि आज की तारीख में हमारे पास इस देश में 80 साल का कोयला उपलब्ध है?

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्या ने तीन बातें पूछी हैं।

श्री जी. किशन रेड्डी : सभापति महोदय, हम कोल माइनिंग के लिए परमिशन लेते हैं, तो उसके लिए forest clearance, environment clearance लेते हैं। यदि माइन्स में trees कट करने पड़ते हैं, तो हम पहले उनको डबल करके, clearance लेने बाद ही कोल माइनिंग शुरू करते हैं। चाहे वह जिधर भी हों, स्टेट गवर्नमेंट उसकी देखभाल करती है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, एन्वायर्नमेंट मिनिस्ट्री उसकी देखभाल करती है। उनकी गाइडलाइन्स के आधार पर clearance होने पर ही माइनिंग शुरू करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी उसकी clearance देती है। Without State Government's clearance, without forest and environment clearance, हम एक भी कोल माइन भी शुरू नहीं करते हैं। उसके बाद ही शुरू करते हैं।

श्री सभापति : आप बाकी दो के बारे में भी बताइए।

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, आंसर नहीं मिला है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister is responding to other two issues also. Bear with him.

श्री जी. किशन रेड्डी : सर, मूल क्वेश्चन तो अलग है। महोदय, अगर आप आदेश देंगे, तो मैं माननीय सदस्या को रिटन में भी जवाब दे सकता हूं।

श्री सभापति : आप थोड़ा और इनिशिएटिव लीजिए। माननीय सदस्या के दोनों बिंदु महत्वपूर्ण हैं। आप आने वाले 15 दिनों में इनसे चर्चा कीजिए। श्री दीपक प्रकाश।

श्री दीपक प्रकाश : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोल इंडिया में कोल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जीपीएस लगाने की बाध्यता है या प्रावधान है? वहां पर जीपीएस सिस्टम को लगाने में जिस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो रही है, वहां जीपीएस लगता नहीं है, जिसके चलते वहां कोयले की तस्करी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जीपीएस सिस्टम ठीक से लगे, इसके लिए मंत्रालय के द्वारा क्या किया जा रहा है?

श्री जी. किशन रेड्डी : सर, माननीय सदस्य ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, तो हम रेलवेज़ के द्वारा और अलग-अलग सिस्टम रोड के द्वारा कोल सप्लाई भी करते हैं। अभी हर साल हमारा कोल सप्लाई का सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है। हम प्रॉपर सिस्टम से कोल सप्लाई को इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी देश में कोल सप्लाई हो, कोल प्रोड्क्शन हो, तो हम हर साल उसको इम्प्रूव करते आ रहे हैं। सर, पावर जेनरेशन कंपनीज़ के पास 21 दिन का कोल अभी भी रिजर्व है, जिससे कोल सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है।

श्री सभापति : 5th सप्लीमेंटरी, श्री राजीव शुक्ला।

श्री राजीव शुक्ला : सभापति महोदय, मेरा सवाल कोल स्कैम के बारे में है। उसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि कोल के जितने ब्लॉक्स थे, उनकी ऑक्शन की गई। ऑक्शन के बाद मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी कितनी माइन्स नॉन ऑपरेशनल हैं, क्योंकि जिन लोगों को ऑक्शन हुआ है, उन्होंने अभी तक उनको टेकओवर नहीं किया है, क्योंकि वे पहले कहीं और थीं और अब एक हजार किलोमीटर दूसरी जगह कर दिया। इसकी वजह से हम कितना कोल इम्पोर्ट कर रहे हैं? I would like to know how much coal are we importing because several mines are non-operational.

श्री जी. किशन रेड्डी : सर, यह क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है।

श्री सभापति : जी, यह रिलेटेड नहीं है।

श्री जी. किशन रेड्डी : सर, माननीय सदस्य को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी डिटेल मेरे पास है, तो मैं उनको इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री राजीव शुक्ला : सर, कोल स्कैम के बारे में है।

MR. CHAIRMAN: Rajeev*ji*, you are a very senior Member. Hon. Minister will get back to you in writing. Is it okay?

Question No.65 as Question No.64 has been withdrawn. ***...(Interruptions)...*** Question No.65, Shri Vaiko ***...(Interruptions)...***

** 64: Question was withdrawn.*

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, क्वेश्चन 64 ड्राप क्यों किया गया?

MR. CHAIRMAN: Leave it to me. There are rules. I only inform the House. If anyone wants to know the background, I will let you know.

Question No.65 - Shri Vaiko ***...(Interruptions)...***

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : लिस्ट होने के बाद क्वेश्चन क्यों ड्रॉप किया गया, कैसे किया गया? इसको पहले ही कर देते? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Let me inform the Leader of the Opposition that this is not for the first time; as a matter of fact, it is very frequent. It is a parliamentary practice. And, the decision is taken by the Chairman. ***...(Interruptions)...*** Question No.65 - Shri Vaiko. ***...(Interruptions)...*** Shri Vaiko is not present. Any supplementaries? ***...(Interruptions)..***

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I have a supplementary on this. ***...(Interruptions)...***

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : मंत्री जी बैठे हुए हैं। ...(**व्यवधान**)... ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो कैसे चलेगा? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Let me tell the hon. Members, I realise my limitations. My limitations have been indicated amply by taking recourse to the ultimate painful constitutional recourse of unseating me. I would appreciate Members not to make insinuations, innuendoes, and I would particularly call upon senior Members to bear

with me. ...*(Interruptions)*... No; what you said is something ...*(Interruptions)*... What Khargeji said, I take severe exception. Now, Q. No. 65.